सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

प्रेस विज्ञप्ति *रांची,दिनांक–29.11.2017*

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने राज्य विकास परिषद् के सदस्य, श्री टी० नन्द कुमार एवं अधिकारियों के साथ हुई बैठक में विस्तृत विवेचना के उपरान्त सर्वसम्मत् से निम्न बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त की :–

1. 12 चयनित प्रक्षेत्रों के लिए 12 अलग–अलग सचिवों के समूह गठित किए जाए, ताकि लक्ष्य को प्राप्त करने में समेकित निर्णय एवं इनके कार्यान्वयन को त्वरित एवं सुस्पष्ट दिशा प्रदान की जा सके।
2. जनता को उपादेय सेवाओं को अधिक प्रभावी रूप से उन्हें त्वरित उपलब्ध कराने के लिए निर्मित व्यवस्था को और अधिक प्रदायी बनायी जाए तथा इसके लिए गठित Digital Platform को सुव्यवस्थित की जाए।
3. सरकारी प्रक्रियाओं को विकेन्द्रित करते हुए इन्हें सुगठित तथा त्वरित करने हेतु प्रभावी उपाय किए जाए।
4. विकास को गति प्रदान करने के लिए सामाजिक संगठनों एवं निजी क्षेत्रों के सहयोग को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की जाए।
5. Target – Allocation Matrix से हट कर Outcome Matrix की व्यवस्था पर काम करने के लिए पदाधिकारियों/कर्मचारियों/आमजनों को व्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, जिसमें सूचना एवं जनसम्पर्क तकनीकों का उपयोग आवश्यक होगा।
6. प्राप्त परिणामों के लिए Impact assessment की प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता होगी, जो सिर्फ लागत–आमद की नहीं बल्कि लक्षित लाभार्थियों को प्राप्त लाभ के आधार पर अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन गठित कर सके।

त्रिवर्षीय कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए श्री नन्द कुमार ने संक्षेप में बताया कि कार्य योजना का approach Sectoral है, न कि विभागीय। यह Target – Allocation Matrix से अलग हटकर परिणाम (Outcome) आधारित है, जिसमें 12 प्रक्षेत्र (Themes) को आधार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 3 Enabling sectors पर भी जोर दिया गया है, जैसे – प्रभावी शासन, सतत् वन प्रबंधन तथा नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदाय में अभिषरण (People centric convergence in delivery mechanism) का विस्तार। इस कार्य योजना में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सामाजिक संगठन, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, शिक्षाविदों एवं जन सामान्य की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी। श्री नन्द कुमार ने उदाहरण के रूप में बताया कि सरकार शौचालयें तो बना सकती है, परन्तु इनका सदुपयोग हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए समाज की पूरी सहभागिता आवश्यक होगी।

विकास आयुक्त, श्री अमित खरे द्वारा बताया गया कि नीति आयोग की तर्ज पर राज्य की 15 वर्षीय Vision, 7 वर्षीय Strategy तथा 3 वर्षीय Action Plan तैयार करने के लिए राज्य में गठित राज्य विकास परिषद् की एक समिति श्री टी० नन्द कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई, जिसने सभी विभागों एवं प्रक्षेत्रों से विमर्श कर त्रिवर्षीय कार्य योजना तैयार की गई है। राज्य में पारम्परिक Budgeting की व्यवस्था से हटकर परिणामोन्मुख (Outcome Oriented) बजट बनाने की ओर यह त्रिवर्षीय कार्य योजना मील का पत्थर साबित होगी।

प्रस्तुत त्रिवर्षीय कार्य योजना का अध्ययन कर 15 दिनों में सभी विभागीय सचिव अपने–अपने सुझाव अपने विभागीय मंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर उपलब्ध कराएँगें, ताकि शीघ्र ही इस कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। त्रिवर्षीय योजना वेबसाईट https://finance-jharkhand.gov.in पर भी उपलब्ध है।

बैठक में मुख्य सचिव, श्रीमती राजबाला वर्मा, राज्य के प्रख्यात अर्थशास्त्री, उप कुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, प्रो० रमेश शरण, डॉ० हरिश्वर दयाल, निदेशक प्रमुख, राजकोषीय अध्ययन संस्थान के अतिरिक्त राज्य के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित थे।